

प्रदेश में मत्स्य उत्पादन दोगुना करने की दिशा में सक्रियता से करें कार्य : सीएम यादव

कृषक कल्याण वर्ष में मत्स्य पालकों की आर्थिक समृद्धि के लिए बनाई जाए कार्य योजना

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग की समीक्षा

भोपाल/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र



मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेश के सभी किसानों और मछुआरों की आर्थिक समृद्धि के लिए संकल्प के साथ कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है, इसके साथ हमें मत्स्य उत्पादन में भी सक्रियता से कार्य कर आने वाले वर्षों में इसे दोगुना करने की दिशा में काम करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मत्स्य पालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए प्रदेश में मछली पालन के साथ ही एकाकल्चर के क्षेत्र में भी कार्य किया जाए। प्रदेश में ऐसा इको सिस्टम तैयार किया जाए, जिससे

मछुआरों का आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार कृषक कल्याण को समर्पित करते हुए यह वर्ष मना रही है। मध्यप्रदेश को मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश का नंबर-1 राज्य बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करें। मछुआ सम्मेलन आयोजित कर मत्स्य पालन में बेहतर कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए। सीड प्रोडक्शन बढ़ाने की दिशा में कार्य करें। प्रदेश में संचालित मत्स्य महासंघ के सुव्यवस्थित उपयोग के लिए भी कार्य करने के निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि कम भू-जल स्तर वाले जिलों में फॉर्म पॉन्ड मॉडल के माध्यम से मत्स्य उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए एक जिले को मॉडल के रूप में तैयार किया जाए, जिसमें मत्स्य उत्पादन के साथ ही सिंचाई, कमल गड्ड, मखाना सहित अन्य एकाकल्चर आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रदेश में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दिशा में मध्यप्रदेश केज कल्चर नीति पर कार्य किया जा रहा है।

इसमें 10 हजार केज हितग्राही मूलक योजना में और 90 हजार केज उद्यमी मॉडल के अंतर्गत तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के विषय में भी अधिकारियों ने विस्तार से जानकारी दी। बैठक में भोपाल में प्रस्तावित विशेष प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एक्का पार्क एंड रिसर्च सेंटर की जानकारी भी दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संभाग स्तर पर ■ शेष पृष्ठ 6 पर

सीएम यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय जनजातीय कार्य और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को वर्ष 2030-31 तक की निरंतरता के लिए 7,133 करोड़ 17 लाख रुपये की स्वीकृति

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत अविद्युतीकृत घरों एवं शासकीय संस्थानों के विद्युतीकरण के लिए 366 करोड़ 72 लाख रुपये की स्वीकृति

उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के आई टी संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों को एक बार के लिए आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की स्वीकृति

म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2026 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन का सार्वशीकरण) नियम 2026 का अनुमोदन

परिवार पेंशन के लिये पात्र सदस्यों में अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा पुत्री भी होगी शामिल

भोपाल/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की



बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक जनजातीय कार्य और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की निरंतरता के लिए 7,133 करोड़ 17 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति अनुसार जनजातीय कार्य विभाग की पीवीटीजी आहार अनुदान योजना के लिए 2,350 करोड़ रुपये, एकीकृत छात्रावास योजना के लिए 1,703 करोड़

15 लाख रुपये, सीएम राइज विद्यालय योजना के लिए 1,416 करोड़ 91 लाख रुपये, आवास सहायता योजना के लिए 1,110 करोड़ रुपये के साथ ही माध्यमिक शिक्षा मण्डल को शुल्क की प्रतिपूर्ति, अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति, कक्षा-9वीं की छात्रवृत्ति के लिए 522 करोड़ 8 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास की

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के लिए 31 करोड़ 3 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे-मातरम् गायन के साथ आरंभ हुई। मंत्रि-परिषद ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JG) अंतर्गत विद्युत अधोसंरचना विस्तार द्वारा 63 हजार 77 अविद्युतीकृत घरों एवं 650 अविद्युतीकृत शासकीय संस्थानों के विद्युतीकरण के लिए

366 करोड़ 72 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें केन्द्र शासन से अनुदान राशि 220 करोड़ 03 लाख रुपये तथा राज्य शासन का अंश 146 करोड़ 69 लाख रुपये का भार आयेगा। इसके अतिरिक्त (म.प्र. ऊर्जा विकास निगम द्वारा) 8 हजार 521 घरों को ऑफ-ग्रिड से विद्युतीकरण के लिए अनुमानित लागत 97 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजना में विद्युतीकरण से संबंधित वितरण प्रणाली निर्माण के लिए योजना लागत की शेष राशि (केन्द्र से प्राप्त अनुदान को छोड़कर) राज्य शासन द्वारा राज्य की वितरण कंपनियों को अंश-पूजी के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी। म.प्र. ऊर्जा विकास निगम द्वारा किए जाने वाले ऑफ ग्रिड विद्युतीकरण (सेलर + बैटरी) के लिए योजना के समस्त व्यय का वहन राज्य शासन द्वारा किया जायेगा। अनुमोदन अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वितरण कंपनी

■ शेष पृष्ठ 6 पर

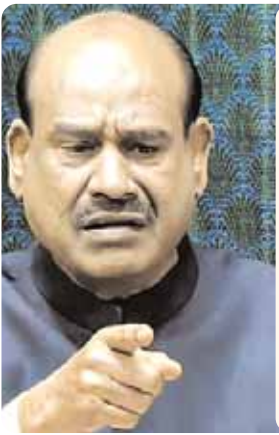
व्यो उठाया गया यह कदम?

विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ने सदन की कार्यवाही में पक्षपाती रवैया अपनाया है और विपक्ष की आवाज को दबाया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड़ा ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। नोटिस देने के लिए कांग्रेस सांसद सुरेश कोडिकुन्निन, गौरव गोमोई, मोहम्मद जावेद लोकसभा महासचिव के पास पहुंचे थे।

पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी आयोग से करेंगे मुलाकात

कोलकाता (वार्ता)। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ से मुलाकात करने वाले हैं। इस बैठक का उद्देश्य राज्य की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने के लिए एक संशोधित तारीख तय करना है, जिससे वर्तमान विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का समापन होगा। यह चर्चा सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर से जारी निर्देश के मद्देनजर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सूची को अंतिम रूप देने से पहले ईआरओ को दावों की जांच करने 14 फरवरी तक समय दें।

लोकसभा स्पीकर बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, विपक्षी सांसदों ने किए हस्ताक्षर



विपक्ष के सौंपे अविश्वास प्रस्ताव के चार बिंदु

- नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया
- विपक्ष के आठ सांसदों को निलंबित कर दिया गया
- बीजेपी सांसद को पूर्व प्रधानमंत्रियों को लेकर आपतिजनक बातें बोलने दी गई
- स्पीकर ने कांग्रेस सांसदों पर साजिश का आरोप लगाया

लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया

नियम: लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 94 और लोकसभा में कार्यप्रणाली और कामकाज के नियमों के अनुच्छेद 200 द्वारा नियंत्रित होती है।

प्रक्रिया: जो सदस्य स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए प्रस्ताव का नोटिस देना चाहता है, वह महासचिव को लिखित में ऐसे प्रस्ताव का पूरा टेक्स्ट देना। प्रस्ताव मंजूर होने के लिए, उसे नीचे दी गई शर्तों को पूरा करना होगा।

क्या लोकसभा में टिक पाएगा अविश्वास प्रस्ताव?

गौरतलब है कि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का पास होना बेहद मुश्किल है। क्योंकि कांग्रेस समेत विपक्ष के पास कुल 220 से ज्यादा सांसद हैं। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष को ज्यादा मशकत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन लोकसभा में इसको पास कराना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां एनडीए को बहुमत है।

आज बेबाक

भारत में ये कैसा लोकतंत्र है? जहां सड़कों पर मारे- मारे घूमने वाले आवारा कुत्तों तक को भौंकने की आजादी है लेकिन प्रातः स्मरणीय और परम पूजनीय माननीयों को बोलने की आजादी के लिए संसद के भीतर और बाहर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। नतीजतन संसद की कार्यवाही ठप पड़ी हुई है। जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई स्वाहा हो रही है। वाकई ये तो बहुत बेईसाफी है। सोचने की बात है कि अगर माननीय बोलेंगे नहीं तो उनका खाया पीया हजम कैसे होगा? लोकतंत्र में सबको अपना गुबार निकालने का मौका दिया ही जाना चाहिए।

एआई जनरेटेड कंटेंट पर लगाना होगा वाटरमार्क

सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जारी किया आदेश

चंडीगढ़/ए। सरकार ने कहा कि अब मानव निर्मित या कृत्रिम रूप से बनाई गई जानकारी को स्पष्ट रूप से पहचान योग्य लेबल (वाटरमार्क) के साथ दिखाना अनिवार्य होगा। इसमें ऑडियो, वीडियो, फोटो या ग्राफिक सहित किसी भी डिजिटल सामग्री को शामिल किया गया है, जिसे कंप्यूटर या किसी संसाधन से बनाया गया, संशोधित किया गया या बदला गया हो।

हर तीन महीने में यूजर के लिए जारी करनी होगी चेतावनी: प्लेटफॉर्म को यूजरों को कम से कम हर तीन महीने में

गेरकानूनी इस्तेमाल पर रोक सुनिश्चित करें प्लेटफॉर्म



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को

यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी यूजर ऐसी सामग्री का गलत इस्तेमाल न करे। अगर कोई यूजर गैरकानूनी, अश्लील, धोखाधड़ी या बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री बनाए या साझा करे, तो प्लेटफॉर्म उसे रोकने के लिए स्वचालित (ऑटोमैटेड) तकनीक का इस्तेमाल करेंगे।

चेतावनी देनी होगी कि नियमों का उल्लंघन करने पर दंड या सजा हो सकती है। यदि कोई नियम तोड़े, तो उसका खाता निलंबित किया जा सकता है या सामग्री को हटाया जा सकता है।

नियमों के उल्लंघन पर तीन घंटे में सूचना देना अनिवार्य: सरकार ने कार्यवाही की समयसीमा भी घटा दी है। पहले 36 घंटे में कार्यवाही करनी थी, अब तीन घंटे में सूचना देना अनिवार्य है। उल्लंघन होने पर प्लेटफॉर्म को तुरंत उचित कार्यवाही करनी होगी। यह कदम डिजिटल मीडिया में सुरक्षा, पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इससे ■ शेष पृष्ठ 6 पर

गरमा-गरम

किताब पर रार



एमओयू: मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी विभाग छत्तीसगढ़ और एसटीपीआई के बीच ऐतिहासिक समझौता

ज्ञान, तकनीक और नवाचार में विशेष पहचान बनाएगा छत्तीसगढ़: साय

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ ज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भी देश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य को ज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। आधुनिक अधोसंरचना, प्रभावी ई-गवर्नेंस प्रणाली और निवेश-अनुकूल नीतियों के चलते छत्तीसगढ़ आज आईटी, आईटीईएस एवं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों के लिए एक भरोसेमंद और आकर्षक गंतव्य के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में



■ सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन की होगी स्थापना

■ प्रदेश में नवाचार, स्टार्ट-अप और कौशल आधारित रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

■ टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों के आकर्षक गंतव्य के रूप में उभर रहा छत्तीसगढ़

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के मध्य हुए महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) उपरांत कार्यक्रम की संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि

युवाओं में उद्यमिता विकसित करने और उन्हें आईटी एवं आईटीईएस जैसे क्षेत्रों में विश्वस्तरीय अवसर राज्य के भीतर ही उपलब्ध कराने की दिशा में यह पहल की गई है। इस एमओयू के तहत राज्य में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप (CoE) एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट (ESDD) सेंटर की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वन एवं औषधीय उत्पाद आधारित मेडटेक, स्मार्ट सिटी समाधान तथा स्मार्ट कृषि जैसे चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार और स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, ■ शेष पृष्ठ 8 पर

तीन दिन के भारत दौरे पर आ रहे फ्रांस के राष्ट्रपति, कई अहम मुद्दों पर होगी बात

नई दिल्ली । फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों 17 फरवरी से तीन दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। यह जानकारी मंगलवार को विदेश मंत्रालय दी। यहां वे एआई इमैक्टे शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेता विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त, नेता इंडो-पैसिफिक में सहयोग सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मोदी और मैक्रों संयुक्त रूप से 'भारत-



■ फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों जल्द भारत के दौरे पर आने वाले हैं

फ्रांस नवाचार वर्ष' का उद्घाटन करने के लिए मुंबई में भी उपस्थित रहेंगे।

ન્યૂજ ગૈલરી

4 साल पहले लॉक हुआ आधार कार्ड अथक प्रयासों के बाद खुला



उध्योग/नवप्रदेश। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा द्वारा जनसुनवाई करते हुए कई आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया तथा शासन की विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को तत्काल लाभान्वित करने के कार्यवाही की गई, इस दौरान नाबालिग निराश्रित बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना में लाभ देने के निर्देश दिये गये, वहीं एक आवेदक को संबल योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त होने के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद, अपर कलेक्टर श्री रूक्मिणी उपाध्याय, एसडीएम श्री गगन सिंह मीणा, डिप्टी कलेक्टर श्री विजय शङ्कर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। जनसुनवाई के दौरान कुल 167 आवेदन प्राप्त हुए। वर्ष 2021 में आधार कार्ड अपडेट कराने की प्रक्रिया के दौरान तकनीकी त्रुटि से बंद हुआ आधारकार्ड कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के प्रयासों से पुनः एक्टिव हुआ और बालिका रशिका जागिड आधार जताने के लिए जनसुनवाई में पहुंची और कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा को चॉकलेट भेंट की गई। आधार कार्ड लॉक होने से परेशान बालिका रशिका जागिड पुत्री श्री रामबाबू जागिड द्वारा वर्ष 2025 में जनसुनवाई के दौरान आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा आधार कार्ड बनाये जाने की मांग की गई थी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा की विशेष पहल पर इस मामले में गंभीरता के साथ ई-गवर्नेंस के माध्यम से आधारकार्ड को एक्टिव करने के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया तथा उच्च स्तर पर किये गये प्रशासनिक प्रयासों के चलते बालिका को आधारकार्ड प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि आधारकार्ड लॉक होने से बालिका 10वीं कक्षा का फार्म भी नहीं भर पा रही थी, छो-छो की प्रतिभावान खिलाड़ी रशिका को आधारकार्ड नहीं होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, आज जब वे अपना आधार हाथ में लेकर जनसुनवाई में पहुंची तो उनकी आंखों में खुशी के साथ ही प्रशानन के प्रतीक कूटना भी थी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा द्वारा कुम्हारपुरा तहसील वीरपुर निवासी दो नाबालिग एवं निराश्रित बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना अंतर्गत लाभ प्रदान करने के निर्देश महिला बाल विकास अधिकारी को दिये गये। बच्चों के साथ आये ग्राम के लोगों ने बताया कि दोनों बच्चों की माँ की मृत्यु हो गई है और पिता जेल में है। ऐसे में बच्चों का जीवन यापन कठिन हो रहा है। इस मामले में स्पॉन्सरशिप योजना अंतर्गत लाभ दिये जाने के निर्देश दिये गये। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा द्वारा प्राप्त जलछेडा निवासी श्री रघुवीर बैरवा को उनके आवेदन परीक्षण उपरत अग्रत कराय़ा गया कि मुख्यमंत्री जनकल्याण संसत् योजना अंतर्गत पत्नी की सामान्य मृत्यु पर दो लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत होकर ईपीओ जारी हो चुका है तथा शीघ्र ही बैंक खाते के माध्यम से राशि प्राप्त होगी। श्री रघुवीर बैरवा द्वारा अपनी पत्नी स्व. श्रीमती कमलेश बैरवा की मृत्यु पर दो लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

**महाशिवरात्रि मेला : छोटा
महादेव में व्यवस्थाओं को लेकर
कलेक्टर-एसपी ने दिए निर्देश**
छोटा महादेव मेले की तैयारियों का निरीक्षण

बैतूल/नवप्रदेश। महाशिवरात्रि के अवसर पर बैतूल जिले के समीप स्थित प्राचीन छोट्टा महबूब मंदिर में दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं सुगम आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए बैतूल कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी एवं पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र जैन ने मंगलवार को मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जांचना लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने मेले के प्रहरी मार्गों का अवलोकन करते हुए कुछ स्थानों पर झाड़ियों की छांटी कराने तथा मार्गों की आवश्यक मरम्मत और समतलीकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए, जिससे वाहनों का आवागमन सुगम हो सके। उन्होंने निर्धारित पार्किंग स्थलों का निरीक्षण कर सुव्यवस्थित पार्किंग प्रबंधन, संकेतक बोर्ड लगाने एवं यातायात व्यवस्था को नियंत्रित रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर: एसपी ने मंदिर परिसर पहुंचकर दर्शन व्यवस्था का अवलोकन किया और निर्देशित किया कि श्रद्धालुओं के लिए निर्धारित मार्ग से ही आवागमन सुनिश्चित कराया जाए। किसी भी अन्य स्थान से पहाड़ी पर चढ़ने से रोकने के लिए आवश्यक बैरिकेडिंग, चेतावनी एवं सूचना डिस्प्ले लगाए जाएं। भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस बल एवं होमगार्ड की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान यह भी निर्देश दिए गए कि मेला क्षेत्र में चिकित्सा की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। दुकानों एवं ठेलों को मुख्य मार्ग से पर्याप्त दूरी पर लगवाने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें और मेले के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी श्री अलित गार्ग जी उपस्थित रहे, उन्होंने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस दौरान कार्यपालन यंत्रों लोक निर्माण विभाग श्रीमती प्रीति पटेल, जिला खनिज अधिकारी श्री मनीष पालीवाल, थाना प्रभारी श्रीमती बबिता धुवे, रीहंत निरीक्षक पुलिस श्री गजेंद्र केन, वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व सभी विभाग शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करें - कलेक्टर

श्रमयोगी मानधन योजना के तहत कोई भी पात्र हितग्राही पंजीयन से न रहे वंचित समस्त राजस्व अधिकारी वित्तीय वर्ष के अंत तक शत प्रतिशत राजस्व वसूली अर्जित करें वृहद स्तर पर शिविर आयोजित कर प्राप्त करे संकल्प से समाधान अभियान के तहत आवेदन समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने की विभागीय योजनाओं, अभियानों और कार्यों की समीक्षा

नर्मदापुरम/नवप्रदेश।
 आयोजित समय सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर ने विभागीय अर्थ-योजनाओं, अभियानों, सीएमएल, हेल्पलाइन, जनसुनवाई सहित अन्य विभाग की कार्यों की समीक्षा की। समय-सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने श्रम-योगी मानधन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत पात्र हितराशिपत्रों का चिह्नकन कर उनका पंजीयन प्रार्थमिकता के आधार पर सुनिश्चितता किया जाए, ताकि अधिक से अधिक क्रमिक योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। कलेक्टर ने समस्त जनपद-पंचायतों के मुख्य कार्यपालन



अधिकारियों तथा नगरीय निकायों के सौम्यओं को निर्देशित किया कि हितवादी पंजीन के लिए विशेष शिबिरों का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि शिबिरों के माध्यम से श्रमिकों को योजना की जानकारी उपलब्ध कराते हुए मौके पर ही पंजीयन की कार्रवाई पूर्ण कराई जाए।

इस दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सम्स्त विभागीय अधिकारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्राप्त लक्ष्यों के अनुरूप उनकी पूर्ति का आकलन करते हुए ऐसे माहों में शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें। उन्होंने विभागवार लक्ष्यों एवं अब तक की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

समय सीमा की बैठक के दौरान पशुपालन विभाग, उद्योग विभाग,

उद्यानिकी विभाग, कृषि विभाग, नगरिय निकाय, जनजातीय कार्य विभाग तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के सहित अन्ध विभागों के अंतर्गत संचालित योजनाओं के शेष लक्ष्यों की समीक्षा कलेक्टर द्वारा की गई। उन्होंने पीएमएफआई योजना के तहत स्वीकृत प्रकरणों में बैंकों से समन्वय स्थापित कर हितग्राहियों को शीघ्र लाभान्वित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने उपसंचालक उद्यानिकी को निर्देशित करते हुए कहा कि लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति हेतु विशेष प्रयास किए जाए। पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने प्रेषित प्रकरणों के विरुद्ध स्वीकृत मामलों की संख्या की समीक्षा करते हुए समस्त पीएमओ को निर्देशित किया कि पात्र हितग्राहियों को पात्रानुसार योजना से जोड़ते हुए

जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का गंभीरता से करें निराकरण: जिला पंचायत सीईओ जैन

**जिला पंचायत सीईओ जैन ने
जनसुनवाई में सुनीं नागरिकों
की समस्याएं**

बैतुल/नवप्रदेश। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अक्षत जैन ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रातः 11 बजे से आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई के दौरान राजस्व, भूमि, जनावन, पेंशन, न्याय, बिजली, पानी सहित अनेक विभागों से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुईं। इस दौरान जिला पंचायत सीओओ श्री अजैन ने कई प्रकरणों में संकेतित अधिकारों से चर्चा कर मौखिक पर ही निराकरण करायी, वहीं शेष मामलों में



समय-सीमा तय करते हुए अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट ने भी नागरिकों की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई में कुल 136 आवेदन

प्राप्त हुए। इस अवसर पर सभी विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। जनसुनवाई में ग्राम मालीतिपटी निवासी दिनेश हनोते ने अनुग्रह सहायता राशि दिलाए जाने के लिए आवेदन दिया। जिस पर जिला

बागचा के विस्थापित तीन हितग्राहियों को मिली 36 लाख रुपये की राशि

कलेक्टर द्वारा बैंक खाते में रिलीज की गई एफडीआर की राशि

इश्यापुर/नवप्रदेश। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अपिंत वर्मा की आमजन के प्रति संवेदशीलता एवं सहृदयता से कार्य करने की शैली के चलते कृनों वन मंडल के बागचा से विस्थापित तीनों हितग्राहियों की 36 लाख रुपये की एफडीआर राशि तत्काल रिलीज किये जाने की कार्यवाही की गई है, तीनों हितग्राहियों की 12-12 लाख की एफडीआर उनके बैंक खातों में राशि जारी करने हेतु बैंक को लिखित में पत्र जारी कर दिया गया है। ग्राम बागचा के विस्थापित श्री दिनेश आदिवासी,



श्रीमती सौमोती आदिवासी, श्री सुखलाललाल आदिवासी निवासी चक बमूलिया (नया बागचा) ने कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को श्री अर्पित वर्मा को अवगत कराया कि विस्थापन अंतर्गत शासन के प्रावधान के क्रम में उनके द्वारा विकल्प एक का चयन किया था, जिसमें उन्हें 15 लाख रुपये की

राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक में कलेक्टर सूर्यवंशी सरख्त

राजस्व वसूली में तेजी लाने और लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

बैतूल/नवप्रदेश। कलेक्टर श्री नेरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी की अध्यक्षता में मंगलवार को तहसील कार्यालय में राजस्व कार्यी कों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने राजस्व वसूली की वर्तमान प्रगति को असंतोषजनक बताते हुए नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रतिदिन राजस्व वसूली में वृद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं समय पर राजस्व जमा नहीं करने वाले बकायादारों को तत्काल नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने विशेष रूप से कॉलोनाइजरों के द्वारा राजस्व जमा न करने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए कि जो कॉलोनाइजर निर्धारित समय में टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कृकी आदिवासी

एचि लेकर कार्य करें, ताकि योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने परिचयना अधिकारी डूड को सभी सीएमओ के साथ नियमित बैठक कर प्रगति की सतत समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। कोलेक्टर ने ईई लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन अंतर्गत हैउओर की गई योजनाओं का क्रियमि रिव्यू किया जाए। अपूर्णताओं में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा किसी भी स्तर पर कमी पाए जाने पर तत्काल सुधारामक कदम उठाए जाएं। कोलेक्टर द्वारा पूर्ण हो चुकी योजनाओं को शीघ्र सन्धिपत पंचायतों को हस्तांतरित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक के दौरान कोलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि आयुष्मान कार्डधारियों को योजना के तहत समुचित एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अस्पतालों द्वारा हितग्राहियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और उपचार में बाधा आने पर तत्काल समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। संकल्प से समाधान अधिनियम की समीक्षा करते हुए कोलेक्टर ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए



सड़कों के गड्ढे ठीक करने के लिए लोकपथ एप का व्यापक उपयोग किया जाए कमिशनर ने संभागीय समय सीमा की बैठक में दिए निर्देश

नर्मदापुरम/नवप्रदेश।

संकल्प से समाधान अभियान गत 12 जनवरी से प्रारंभ है यह अभियान चार चरणों में आयोजित किया जा रहा है। प्रथम चरण 12 जनवरी से 16 फरवरी तक, द्वितीय चरण 16 फरवरी से 16 मार्च तक, तृतीय चरण 16 मार्च से 26 मार्च तक एवं चतुर्थ चरण 26 मार्च से 31 मार्च तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 16 विभाग की 65 योजनाओं में हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा साथ ही इन योजनाओं से संबंधित शिकायतों का भी प्राथमिकता से निराकरण किया जाएगा।

नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत हितग्राहियों के अधिक से अधिक आवेदन लेकर उनका निराकरण कर संकल्प से समाधान पोर्टल पर निराकरण की स्थिति अपलोड करें। कमिश्नर ने बताया कि 15 मार्च से कलस्टर लेबल पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में भी नवीन आवेदन प्राप्त कर निराकरण किया जाएगा। बताया गया कि अभियान के अंतर्गत अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, कृषि, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उद्यमिकी, नगरीय विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जिला परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, श्रम, सहकारिता, विद्युत विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित 65 योजनाओं के

आवेदन प्राप्त कर प्राथमिकता से निराकरण किए जाएंगे। कमिश्नर श्री तिवारी ने सोमवार को आयोजित संभागीय समय सीमा की बैठक में निर्देश दिए की लोक निर्माण विभाग के लोकपथ एप का आम जनता में ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए, बताया गया कि सड़कों पर स्थिर गड्ढों को ठीक करने के लिए लोकपथ एप बनाया गया है, कोई भी व्यक्ति सड़क के गड्ढे का मौके पर ही फोटो खींचकर लोकपथ एप में अपलोड कर सकेंगे जैसे ही फोटो अपलोड होगा उसके चार दिवस के अंदर लोक निर्माण विभाग उस सड़क के गड्ढे को प्राथमिकता से ठीक करेगा। कमिश्नर ने कहा कि सभी व्यक्ति लोक पथ एप अनिवार्य रूप से डाउनलोड करें और अपने आसपास सड़कों पर दिख रहे गड्ढों की फोटो खींचकर लोकपथ एप पर अपलोड करें जिससे सड़कों के गड्ढे प्राथमिकता से ठीक किए जा सकेंगे। कमिश्नर ने सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए की वे सभी विभागीय बजट का उपयोग आवश्यकता के अनुसार 31 मार्च तक करना सुनिश्चित करें और उसके पश्चात भी यदि बजट बच रहा है तो उसे तत्काल शासन को वापस करें ताकि दूसरे विभाग उसका उपयोग कर सकें। कमिश्नर ने सीएम हेल्पलाइन में लगे प्रकरणों को अटेंड न करने वाले विभागीय अधिकारियों पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिए की सीएम हेल्पलाइन में लगे हर प्रकरण को अटेंड कर उसका निराकरण किया जाए, नान अटेंडेड प्रकरण यदि कोई अटेंड नहीं कर रहा है तो वह मामा नहीं किया जाएगा। कमिश्नर ने प्रधानमंत्री विश्वकर्म योजना, डॉ भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना एवं अन्य योजनाओं में दिए गए लक्ष्य की पूर्ति इसी वित्तीय वर्ष में करने के निर्देश दिए

न्यूज गैलरी

भोपाल में नया अजूबा...हाईटेशन पोल के नीचे निकली सड़क

90 डिग्री ब्रिज के बाद एफिल टावर सड़क; कई साल से बना खतरा



भोपाल/नवप्रदेश। भोपाल में 90 डिग्री एंगल वाले ऐशबाग ब्रिज और ठिगने मेट्रो स्टेशन के बाद एक और नया अजूबा सामने आया है। राजधानी के करोड़ इलाके में हाईटेशन लाइन के टावर (पोल) के नीचे से सड़क निकाल दी गई, जो किसी एफिल टॉवर सड़क की तरह है। मामला सामने आने के बाद अब यह पोल सुखिया बंदोर रहा है। करोड़ की विनायक कॉलोनी में कई साल से हाईटेशन का पोल एफिल टावर जैसा खड़ा है, लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि इसके नीचे से ही सड़क भी निकाल दी गई। लोग पैदल चलने के साथ अपनी कार और मोटरसाइकिलों से आना-जाना भी करते हैं। ऐसे में हाईटेशन लाइन के चपेट में आने का डर बना रहता है।

कई साल से खड़ा

करोड़ के महेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि यह पोल उन्हीं के वार्ड में हैं, जिसे वे कई साल से देखते आ रहे हैं। पहले आसपास रहवासी इलाका नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे आबादी बसने लगी। वर्तमान में अच्छी आबादी यहां रहती है। इस तरह खतरा बढ़ गया है।

बारिश में करंट फैलने का डर

रहवासियों ने बताया कि टावर के नीचे से बड़ी गाड़ियां नहीं निकल पाती। दूसरी ओर, बारिश के दिनों में करंट फैलने का डर रहता है। भोपाल राजधानी है, सरकार को हाईटेशन लाइन और टावर को लेकर ध्यान देना चाहिए। दोनों को ही शिफ्ट किया जाना चाहिए।

बिजली कंपनी हटाने के प्रयास में जुटी

दूसरी ओर, बिजली कंपनी भी इस टावर को अन्य जगह शिफ्ट करने में लगी है। कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन ये टावर और हाईटेशन लाइन नहीं हट पाई। सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद यह टावर फिर से सुर्खियों में आ गया है।

सीएम यादव ने विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्व. शुक्ल की जयंती पर किया नमन

मध्यप्रदेश विधानसभा भवन में की पुष्पांजलि अर्पित

विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने भी किया स्मरण

भो पाल /नवप्र देश।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्व. राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की जयंती पर विधानसभा परिसर में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, पूर्व मंत्री श्री पी.सी. शर्मा, पूर्व विधायक श्री सुदर्शन गुप्ता और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्व. शुक्ल के परिजन ने भी चित्र पर पुष्पांजलि की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि 10 फरवरी 1930 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जन्मे श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, वर्ष 1985 से 1990 तक मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे। उन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पदयात्राओं के

माध्यम से जन जागरण का कार्य किया। लोकप्रिय जन नेता रहे श्री शुक्ल राज्य सरकार में विधि-विधायी एवं सामान्य प्रशासन मंत्री भी रहे। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद, उन्होंने 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2003 तक छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। स्व. राजेंद्र प्रसाद शुक्ल ने अरसंसदीय अभिव्यक्तियां नामक पुस्तक की संकल्पना की, जो विधायी कामकाज पर एक

महत्वपूर्ण संदर्भ है। उन्होंने संसदीय मामलों सहित कई पुस्तक लिखीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रहे व्यक्तियों की जयंती और पुण्यतिथि पर मध्यप्रदेश विधानसभा भवन में उन्हें स्मरण करने की परंपरा स्थापित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर की सराहना करते हुए उनका आभार माना।



बुलाई है, जिसमें बजट सत्र के दौरान भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति और रूपरेखा तय की जाएगी।भोपाल स्थित 74 बंगला के बी-12 (ए) में शाम 7-30 बजे होने वाली इस बैठक में कांग्रेस विधायक प्रदेश से जुड़े जनहित के बड़े मुद्दों पर मंथन करेंगे। उमंग सिंघार ने साफ किया है कि कांग्रेस बजट सत्र में भाजपा सरकार की नाकामियों को पूरी मजबूती से विधानसभा में उठाएगी और हर सवाल पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि बैठक में

सेफर इंटरनेट डे 2026 पर एआई और साइबर जोखिमों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिये रहे जागरूक

भोपाल/नवप्रदेश।

सेफर इंटरनेट डे-2026 के अवसर पर इस वर्ष की निर्धारित थीम एआई और उभरते साइबर जोखिम के तहत राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) मध्यप्रदेश राज्य इकाई द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को इंटरनेट के सुरक्षित, जिम्मेदार और जागरूक उपयोग के लिए प्रेरित करना रहा।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तकनीकी शिक्षा निदेशालय के आयुक्त श्री अवधेश शर्मा उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी श्री कमलेश

जोगी ने की। इस अवसर पर एनआईसी राज्य इकाई के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सहभागिता की। साथ ही प्रदेश के सभी शासकीय एवं स्वायत्त इंजीनियरिंग तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षक एवं विद्यार्थी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने पर जोर दिया। वक्ताओं ने बताया कि वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग जहां विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है, वहीं इसके दुरुपयोग से साइबर अपराधों



के नए स्वरूप सामने आ रहे हैं। एआई-सक्षम धोखाधड़ी, डीपफेक तकनीक, वॉयस क्लोनिंग, व्यक्तिगत संदेशों के माध्यम से ठगी और स्वचालित साइबर हमलों जैसे खतरों

के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने साइबर स्वच्छता की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए मजबूत पासवर्ड का उपयोग, संधिध लिंक या

संदेशों से सावधानी, सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा करने से बचाव तथा नियमित रूप से डिजिटल उपकरणों के अपडेट रखने जैसे उपायों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में नागरिकों को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के प्रति जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर बताया गया कि सेफर इंटरनेट डे प्रत्येक वर्ष फरवरी के दूसरे मंगलवार को विश्व के लगभग 160 देशों में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को इंटरनेट एवं डिजिटल तकनीक के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम के

तहत प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्रशासन एवं राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र के सहयोग से विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और कार्यालयों में जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों, युवाओं एवं आम नागरिकों को साइबर सुरक्षा और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार के प्रति प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सुरक्षित डिजिटल वातावरण के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया गया तथा नागरिकों से साइबर अपराधों से बचाव के लिए सतर्क और जागरूक रहने की अपील की गई।

भोपाल में बाथरूम में मिला एमबीबीएस छात्रा का शव: पास ही पड़ी थी एसिड बॉटल

गांधी मेडिकल कॉलेज में 4 महीने पहले एडमिशन लिया था

भोपाल/नवप्रदेश।

भोपाल में एमबीबीएस छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। गांधी मेडिकल कॉलेज की छात्रा रोशनी का शव बाथरूम में पड़ा था। पास ही एसिड की बोतल भी मिली है। रोशनी ने पिछले साल ही अक्टूबर में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। जानकारी के मुताबिक, रोशनी डे-स्कॉलर थी और कोहेफिजा थाना क्षेत्र में प्राइवेट हॉस्टल में रह रही थी। जब वह सुबह कॉलेज के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, तो साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उसे बुलाने के लिए पहुंचे।

जवाब नहीं मिला तो तोड़ा दरवाजा

छात्राओं के मुताबिक, रोशनी को कई बार आवाज दी। उसे फोन कॉल किया, लेकिन रोशनी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद पीजी के गार्ड को सूचना दी। गार्ड पहुंचा तो पहले कमरे और फिर बाथरूम का दरवाजा तोड़ा गया, जहां रोशनी पड़ी मिली।



पास में मिली संदिग्ध बोतल

स्टूडेंट्स ने बताया कि रोशनी के पास एक खाली एसिड की बोतल भी पड़ी हुई थी। फौरन कॉलेज प्रबंधन को सूचना दी गई। रोशनी को सुबह करीब 8-30 बजे हमीदिया अस्पताल के इमरजेंसी मेडिसिन विभाग ले जाया गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

आलीराजपुर की थी, पिछले हफ्ते ही भोपाल लौटी थी

रोशनी आलीराजपुर की रहने

वाली थी। साथी छात्रों ने बताया कि वह पिछले हफ्ते ही घर से लौटकर भोपाल आई थी। वह पढ़ाई को लेकर गंभीर और शांत स्वभाव की थी।

डीन ने कहा- पढ़ाई को लेकर टेंशन में थी रोशनी

गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन कविता एन. सिंह ने बताया कि रोशनी के मोबाइल में परिजन को भेजे गए मैसेज से पता चला है कि वह पढ़ाई को लेकर तनाव में थी। मेहनत करने के बावजूद ठीक से समझ नहीं पा रही

थी।

पोस्टमॉर्टम के बाद सामने आएगी मौत की वजह

फिलहाल रोशनी के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भोपाल के मसूरी क्षेत्र स्थित मॉर्चुरी भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले की सूचना परिजनों को दे दी है। घटना को लेकर कोहेफिजा पुलिस जांच कर रही है। मौत के कारणों का पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। कोहेफिजा थाना प्रभारी कृष्ण गोपाल शुक्ला ने बताया कि

अलीराजपुर निवासी 19 वर्षीय रोशनी ने अक्टूबर माह में गांधी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था। वह कोहेफिजा इलाके में एक घर में पेइंग गेस्ट के रूप में रह रही थी। बताया जा रहा है कि पढ़ाई ठीक से समझ में न आने के कारण वह लगातार तनाव में थी और सहपाठियों से भी अपनी परेशानी साझा करती रहती थी। मंगलवार सुबह जब रोशनी तय समय पर कॉलेज जाने के लिए कमरे से बाहर नहीं निकली, तो साथ रहने वाली छात्राओं को चिंता

कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव: 12 से 21 फरवरी तक यातायात डायवर्जन लागू



भो पाल /नवप्र देश। कुबेरेश्वर धाम में आयोजित होने वाले रुद्राक्ष महोत्सव और शिव महापुराण कथा के महेनजर जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए यह डायवर्जन 12 फरवरी की सुबह 6 बजे से 21 फरवरी की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।

भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग

भोपाल की ओर से देवास और इंदौर जाने वाले भारी वाहनों को थाना परबलिया क्षेत्र के मुबारकपुर जोड़ और थाना खजुरी क्षेत्र के तुमड़ा जोड़ से श्यामपुर-कुरावर-ब्यावरा-शाजापुर-मक्सी मार्ग से निकाला जाएगा। इसी तरह

देवास और इंदौर से भोपाल आने वाले भारी वाहन मक्सी-शाजापुर-ब्यावरा-कुरावर-श्यामपुर होते हुए भोपाल पहुंचेंगे।

छोटे और सवारी वाहनों की व्यवस्था

भोपाल से आष्टा, देवास, उज्जैन और इंदौर जाने वाले छोटे व सवारी वाहन सीहोर के न्यू क्रिस्टें चौराहा से भाऊखेड़ी जोड़ होते हुए अमलाहा मार्ग से अपने गंतव्य तक जाएंगे। वहीं इंदौर, उज्जैन और देवास से भोपाल आने वाले वाहन आष्टा-अमलाहा-भाऊखेड़ी जोड़-न्यू क्रिस्टें चौराहा मार्ग का उपयोग करेंगे। भोपाल, इंदौर, देवास और उज्जैन से कुबेरेश्वर धाम कथा स्थल आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों पर कोई डायवर्जन लागू नहीं होगा।

भोपाल में लव जिहाद में इस्तेमाल 3 कारें जब्त: आरोपी बोला- छात्रा के वीडियो दो दोस्तों को भेजे

फोन तोड़कर अजमेर में फेंका था

भोपाल/नवप्रदेश। भोपाल में 11वीं की छात्रा से रेप, लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग सहित अश्लील वीडियो वायरल करने के सह आरोपी माज खान से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। सोमवार रात उसकी निशानदेही पर तीन कारें-मारुति सियाज, स्विफ्ट और होंडा सिटी जब्त कर ली गई। इन सभी कारों में अलग-अलग जगहों पर माज के साथी ओसाफ अली खान ने छात्रा के साथ रेप किया था। थार की तलाश में कोहेफिजा थाने की एक टीम खाना हुई है। इसे जल्द जब्त करने का दावा किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि माज अपने मोबाइल को लेकर लगातार गुमराह कर रहा है। उसका कहना है कि वह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जियारत के लिए अजमेर गया था। वहां जैसे ही लव जिहाद केस में अपना नाम आने की जानकारी मिली, उसने मोबाइल फोन तोड़कर जंगल में फेंक दिया। हालांकि, पूछताछ में उसने छात्रा की वीडियो अन्य दो दोस्तों के साथ शेयर करने की बात मानी है। पुलिस अब उन्हें भी नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब करेगी। आरोपियों ने अन्य छात्राओं को तो निशाना नहीं बनाया,



इसकी तहकीकात की जाएगी। बता दें कि रविवार को कोहेफिजा थाना पुलिस ने माज को कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उसे 13 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर सौंपा है।

खानूगांव में कार के अंदर छात्रा से किया था रेप

दरअसल, 2 जनवरी को कोहेफिजा पुलिस ने 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। पीड़िता ने खानूगांव इलाके में कार में रेप करने, धर्म बदलने का दबाव बनाने और अश्लील

वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोप लगाए थे। पुलिस ने इस मामले में 3 जनवरी को ओसाफ अली खान (19) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 8 फरवरी को दूसरे आरोपी माज खान की गिरफ्तारी की गई। वारदात में इस्तेमाल काले कांच की थार, माज की ही थी। पूरा घटनाक्रम उसकी जानकारी में था।

माज का बड़ा भाई एमडी तस्करी केस में जमानत पर है

माज का बड़ा भाई मोनिस मादक पदार्थों की तस्करी मामले में जमानत पर है।

मोनिस का एमडी तस्करी, लव जिहाद और जमीन कब्जा करने वाले यासीन मछली गैंग से रिश्ता भी सामने आ चुका है। वहीं, माज खुद को एक प्रतिष्ठित जिम का संचालक बताता है। पुलिस उसके फोन की सीडीआर डिटेल खंगाल रही है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट का भी परीक्षण कराया जा रहा है।

पुलिस बोली- थार के बारे में जानकारी नहीं दे रहा माज

कोहेफिजा थाने के प्रभारी कृष्ण गोपाल शुक्ला ने कहा- माज खान लगातार गुमराह कर रहा है। उसने बताया कि मोबाइल को तोड़कर अजमेर में फेंका है। थार के संबंध में भी जानकारी नहीं दे रहा है। दो अन्य संदेहियों के नाम उसने बताए हैं। हम उनसे पूछताछ की तैयारी कर रहे हैं। कोहेफिजा पुलिस की जांच में यह भी साफ हो गया है कि हेड कॉन्स्टेबल ज्ञानेंद्र द्विवेदी माज को थाने की गोपनीय सूचना लीक करता था। यही कारण है कि माज पुलिस दबिश से पहले ही भाग निकलता था। पुलिस को ज्ञानेंद्र के माज के साथ 7 फरवरी को वीआईपी रोड स्थित बड़े होटल में लंच करने के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं।

मध्य प्रदेश बजट सत्र से पहले कांग्रेस की बनेगी रणनीति, उमंग सिंघार ने बुलाई विधायक दल की अहम बैठक

भोपाल/नवप्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति तेज कर दी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 16 फरवरी को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें जनहित के मुद्दों पर मंथन होगा। सत्र का मुख्य आकर्षण 2026-27 का बजट रहेगा, जिसमें महिलाओं और युवाओं के लिए बड़ी घोषणाओं की संभावना है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 16 फरवरी को भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक

बुलाई है, जिसमें बजट सत्र के दौरान भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति और रूपरेखा तय की जाएगी।भोपाल स्थित 74 बंगला के बी-12 (ए) में शाम 7-30 बजे होने वाली इस बैठक में कांग्रेस विधायक प्रदेश से जुड़े जनहित के बड़े मुद्दों पर मंथन करेंगे। उमंग सिंघार ने साफ किया है कि कांग्रेस बजट सत्र में भाजपा सरकार की नाकामियों को पूरी मजबूती से विधानसभा में उठाएगी और हर सवाल पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि बैठक में



बेतहशा कर्ज, इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतें, किसानों का समर्थन मूल्य, मुताबिक मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की

ओलावृष्टि से फसल नुकसान, युवाओं का रोजगार, आदिवासी-दलितों पर बढ़ते अत्याचार और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस इन मुद्दों को विधानसभा में हथियार बनाकर सरकार को कटवरे में खड़ा करेगी।

बजट होगा सबसे खास आकर्षण

इस सत्र का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट होगा। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस सरकार के बजट में

सरकार इस बार महिलाओं और युवाओं को साधने के लिए बजट में बड़ी घोषणाएं कर सकती है। खास तौर पर लाइली बहना योजना के लिए करीब 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने की संभावना जताई जा रही है, जो पिछले साल के 18,669 करोड़ रुपये से कहीं ज्यादा होगा। इसके अलावा लखपति दीदी योजना, महिला स्व-सहायता समूहों और युवाओं के स्वरोजगार से जुड़ी नई योजनाएं और घोषणाएं भी बजट का हिस्सा हो सकती हैं। ऐसे में बजट को लेकर सत्ता और विपक्ष, दोनों की नजरें टिकी हुई हैं।

हंगामेदार रहने के आसार

16 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। इसके बाद सरकार अनुरूपक बजट, मुख्य बजट और कई अहम विधेयक सदन में पेश करेगी। वहीं विपक्ष भी कानून-व्यवस्था, एंबुलेंस सेवाओं की बढहाली, बेरोजगारी और जनहित के अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। करीब 19 दिनों तक चलने वाला यह बजट सत्र काफी गहमगहमी भरा रहने की उम्मीद है। सत्ता पक्ष की घोषणाओं और विपक्ष के तीखे सवालों के बीच विधानसभा में तेज सियासी टकराव देखने को मिल सकता है।



सुविचार

जिंदगी में थोड़ी तपिश भी जरूरी है क्योंकि अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छांव में होती है

पाक और चीन को करारा झटका

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के दौरान ही अमेरिका ने एक नक्सा जारी किया है जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर और लद्दाख के अलावा अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दुनिया गया है। यह नक्शा अमेरिका के युएसटीआर ने जारी किया है और इस नक्शे के जरिए भारत व अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौते के दायरे को समझाने की कोशिश की गई है। अमेरिका द्वारा पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताया जाना पाकिस्तान और चीन के लिए करारा झटका है। गौरतलब है कि पीओके को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तथा अक्साई चीन को लेकर भारत और चीन के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। खासतौर पर पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर भारत व पाक के बीच तलवारे खींची हुई है। जबकि पाकिस्तान अभी भी जम्मू कश्मीर को लेकर सारी दुनिया में हाथ तोबा मचाते हुए घुम रहा है और उसने संयुक्त राष्ट्र संघ सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचो पर अक्सर कश्मीर का बेसूरा राग अलावा है। जिसका भारत ने हर बार मुंहतोड़ जवाब देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहगा। इस मुद्दे पर न तो भारत पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत करेगा और न ही किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त करेगा। भारत तो अब पीओके को भीलेकर रहेगा जिसपर पाकिस्तान ने दशकों से अवैध कब्जा कर रखा है। अब अमेरिका द्वारा पीओके को भारत का हिस्सा बताया जाने से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। खासतौर पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के लिए तो यह शर्मिंदगी की बात है जो अमेरिका से यह गुहार लगाते रहे हैं कि वह पीओके को पाकिस्तान के हिस्से के रूप में मान्यता प्रधान करें। अमेरिका ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर कर रख दिया है और अब एक बार फिर पीओके को भारत में शामिल करने की कवायद तेज हो सकती है। अमेरिका के इस रुख से पाकिस्तान और चीन की बड़ी कुत्सीतिक हार हुई है जो उनके लिए गहरे सदमें से कम नहीं है। उल्लेखनीय है कि पांच साल पहले पाकिस्तान ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था जिसमें उसने पाक अधिकृत कश्मीर तथा लद्दाख के कुछ हिस्सों को पाकिस्तान का बताया था। इसी तरह चीन ने भी तीन साल पहले अपना नया नक्शा जारी किया था। जिसमें उसने अरूणाचल प्रदेश को तथा अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया था और भारत से कहा था कि वह इसे तुरंत खारी कर दे। भारत ने पाकिस्तान और चीन दोनों के ही नक्शों को नकार दिया था।

अब ओवैसी यूपी में बिगाड़ेंगे खेल

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईए ने अब उत्तरप्रदेश में भी ताल ठोकने के संकेत दे दिये हैं। हालांकि अभी उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव में लगभग दो साल का समय शेष है। लेकिन एआईएमआईए ने अभी से वहां दस्तक देने की योजना बना ली है। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबररूद्दीन ओवैसी ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ललकारा है कि वे उत्तरप्रदेश आ रहे हैं। हालांकि छोटे ओवैसी की इस चुनौती को योगी आदित्यनाथ गंभीरता से नहीं लिया है और उनके वक्तय को हवा में उड़ा दिया है। वैसे भी योगी आदित्यनाथ जानते है कि ओवैसी की पार्टी उत्तरप्रदेश में भाजपा का खेल बिगाड़ ही नहीं सकती उन्टे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में इसका प्रमाण मिल ही चुका है। वहां एआईएमआईए के चुनाव लड़ने से एनडीए को ही फायदा हुआ था जिसने तीन चौथाई बहुमत हासिल कर लिया था जबकि ओवैसी के कारण मुस्लिम वोटों का बिखराव होने से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचा था। यदि ओवैसी उत्तरप्रदेश में भी चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गणित गड़बड़ा सकता है। उत्तरप्रदेश में एआईएमआईए के उत्तरप्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने तो यह ऐलान कर दिया है कि यदि उत्तरप्रदेश में एआईएमआईए के हाथों में रिमोट कंट्रोल आएगा तो वह उत्तरप्रदेश में पहली बार एक बुंके वाली मुस्लिम महिला को मुख्यमंत्री बनाएँगे। गौरतललब है कि एआईएमआईए ने किसी मुस्लिम को उपमुख्यमंत्री बनाने का दांव खेला था और उसे मुस्लिम दांव का भरपूर समर्थन मिला था। ऐसे में यूपी में किसी मुस्लिम महिला को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा सपा और कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध हो सकता है।



सद्गुरु बोधामृतम्

♦ राजी तेरी रजा में रहना; किसकी रजा में ? आत्मा की रजा में। अपने आत्मा से राजी रहो कि कभी गुस्सा भी आए तो अपनी आत्मा पर आए, उसी से भिड़ना, उसी से लड़ना, पटकना, मारना तो अपनी आत्मा से और आत्मा की जो पुकार है उसे सुना करो। आत्मा सिर्फ आनंद चाहती है।

आज का इतिहास

नई दिल्ली। 1933 - ग्रीष्म की 'हरिजन वीकली' का प्रकाशन शुरू हुआ । 1942 - प्रसिद्ध समाजसेवी जन्मलाल बजाज का निधन। 1944 - जर्मन सेना ने इटली के अप्रिलिया पर दोबारा कब्ज़ा किया। 1950 - भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ राव इन्द्रजीत सिंह का जन्म। 1959 - भारतीय क्रिकेटर चीन्ू मार्कंड ने अपना आखिरी टेस्ट वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में खेला। 1975 - मारिस्ट थैचर ब्रिटिश कंवेन्टिव पार्टी की पहली महिला नेता चुनी गई। 1987 - अमेरिका ने नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया। 1990 - दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत नेता नेल्सन मंडेला 28 वर्षो बाद जेल से रिहा किये गए। 1997 - भारतीय खगोल भौतिकविद डॉ जयंत वी. नार्लीकर 1996 के यूनेस्को के 'कलिंग पुरस्कार' से सम्मानित। 1998 - 'आपरेशन बीच' के तहत अंडमान के एक द्वीप में अंतरराष्ट्रीय गिरोह के छह सदस्य मारे गए और 74 गिरफ्तार हुए। 1999 - चीन द्वारा रूस से 20 सुखोई लड़कू विमान खरीदने की घोषणा।



प्रेम शर्मा

आजादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं और नीति नियंताओं ने काफी सोच-विचार कर समाज और देश के विकास का सपना देखा था। तब हमारी गिनती एक मुठे-पिटे गरीब देशों में होती थी। आज हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होने का दावा करते हैं, लेकिन नैतिक तौर पर तेजी से पाताल की ओर गिरते जा रहे हैं। सबसे खास बॉत यह कि आज का दौर डिजीटल मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है। इस दौर में सामान्य विधायक से लेकर खास विधायक सांसद, मंत्री, नेता सदन, नेता विपक्ष, स्पीकर तथा अन्य जिम्मेदारों की बात, खगमा किसी ना किसी तरीके से आम जनता को देखने,सुनने मिल जाते है। उनका पक्षपात, जनता के प्रति गैरजिम्मेदारी भरा बयान या हरकत सबकुछ रिकार्ड होती रहती है इसके बावजूद सत्तापक्ष और जिस तरह जनविरोधी आचरण सदनो में कर रहा है वह भगवान तुल्य कहे जाने वाले मतदाता और आम जनता के साथ सीधे धोखा है। यानि इतना तय है कि जनता के प्रति अपनी जबाबदेही के लिए पक्ष विपक्ष अपने आप को अलग नहीं बता सकता।



एस. पी. तिवारी

वर्तमान संदर्भ में, भारतीय केंद्रीय श्रमिक संघों को, जो धीरे-धीरे अपना प्रभाव खो रहे हैं, आत्मविश्लेषण करने और अन्यत्र अपनाई जाने वाली अधिक प्रगती और दूरदर्शी तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है। भारतीय श्रमिक को एक समग्र दृष्टिकोण के साथ संगठित किया जाना चाहिए, जो जीवन यापन में आसानी, सामाजिक सुरक्षा और सकारात्मक सहभागिता पर जोर देता हो। विवादों का समाधान टकराव के बजाय संवाद के माध्यम से करना यह सुनिश्चित करेगा कि परिचालन प्रक्रिया बाधित न हो और राष्ट्रीय विकास की गति सुचारु रूप से जारी रहे। केवल ऐसे संतुलित और व्यावहारिक राजनीतियों के जरिये ही श्रमिकों के अधिकारों को वास्तविक रूप में मजबूत और दीर्घावधि में सुरक्षित किया जा सकता है।

पाठकों की बात



बहुत बार सोचता हूँ कि हम क्या हैं ? एक अंगुवा या फिर सत्ता की भट्ठी में पड़ा एक गोबर का उपला अभी हम चुप हैं अपनी तपिश छिपाए हम गोबर गणेश नहीं हम जानते हैं उपयोगिता जलाने के बाद भी अपनी राख बिखेर दी जाएगी खेतों में खाद की तरह कहर में भी उगाएँगे अन्न या रागड़े जाने पर चमकाएंगे बर्तन काले चेहरे वाले हम जानते हैं यह भी कि तुम्हारा अंतिम सपना भी हमारे बिना पूरा न होगा उपले हैं गोबर के हम सुरागले तो जला डालेंगे

- केदार नाथ शब्द मसीहा



एक आकड़े के अनुसार एक घंटे अगर केन्द्र सरकार के सदन में हंगामा हो जाए तो 1.5 करोड़ और विधानसभाओं में लगभग 25 से 50 लाख रूपये बर्बाद होते है जो जनता के टैक्स का पैसा होता है।

यह स्थिति केवल संसद में नही बल्कि विधानसभाओं में भी लगातार जारी है। एक समय था कि जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन दलगत पार्टी से हटकर जनहित में निभाते थे। अब योजनाओं पर विचार करने के बजाय कुछ ऐसे मुद्दों पर बस चल रही है। अब हमें यह कहने में संकोच होता है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है।

यह वही भारतीय संसद है जहां 1950 के दशक में एक नए सांसद अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की आलोचना पर प्रधानमंत्री जी विचलित नहीं हुए बल्कि उस युवा सांसद के पास जाकर उसके भाषण की तारीफकी और यह कह दिया कि तुम एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री बनोगे और वही युवा सांसद अटल बिहारी वाजपेयी जब देश का विदेश मंत्री बना तो उसने देखा कि उनके कार्यालय जो साउथ ब्लॉक में स्थित था से नेहरू जी की फोटो गायब थी जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई और पंडित नेहरू की फोटो वहां पर फिर लगावा दी गई। यह वही भारत है जब 1991 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का पक्ष रखने के लिए अपनी पार्टी से कोई नहीं मिला तो उन्होंने नेता विपक्ष अटल बिहारी वाजपेई को जिनेवा में भारत का पक्ष रखने के लिए भेजा। आज लोकसभा और राज्यसभा से लेकर विधानसभाओं तक में बहस का स्तर इतना गिर गया है की समझ में नहीं आ रहा कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली कहां जा रही है।सांसद और विधानसभओं में बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, बिजली और पानी की कमी, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मुद्दों को लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ मजबूती से उठाया जाना चाहिए।संसद में जनहित के मुद्दों पर गंभीर

हड़ताल श्रमिक अधिकारों को कमजोर करती है

चार नयी श्रम संहिताओं का क्रियान्वयन, भारत की विशाल श्रम शक्ति, विशेष रूप से अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए जीवन यापन में आसानी में सुधार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन सुधारों का उद्देश्य, बिना जटिल उद्योग वर्गीकरण की बाधाओं के, सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देना है। प्रत्येक श्रमिक के लिए अनिवार्य पहचान पत्र की शुरुआत करते हुए, ये संहिताएं उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभों तक सीधी पहुंच की सुविधा के साथ सशक्त बनाने का प्रयास करती हैं। नियमित और अनिवार्य स्वास्थ्य जांच, श्रमिकों की भलाई में मदद करेंगी, जिससे वे स्वस्थ और अधिक उत्पादक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इसके अलावा, समयबद्ध शिकायत निवारण व्यवस्था, पीड़ित श्रमिकों द्वारा सामना किए जाने वाले मानसिक तनाव और अनिश्चितता को कम करने में सहायता करेगी। समग्र रूप से, ये उपाय भारतीय श्रमिकों के लिए गरिमा, सुरक्षा और समावेशी विकास पर केंद्रित एक प्रगतिशील रूपरेखा का प्रतिनिधित्व करते हैं।

हालाँकि, इन सकारात्मक प्रावधानों के बावजूद, राजनीतिक रूप से प्रेरित केंद्रीय श्रमिक संघों (ट्रेड यूनियन) का एक हिस्सा अक्सर हड़ताल के प्रतिकूल प्रभाव पर पूरी तरह विचार किए बिना, हड़ताल पर उतर आता है। ऐसी हड़तालों से विशेष रूप से असंगठित अर्थव्यवस्था के लगभग 38 करोड़ श्रमिकों के पारिश्रमिक को भारी नुकसान होता है, जो अपनी जीविका के लिए दैनिक आय पर निर्भर होते हैं। उनके मुद्दों को हल करने के बजाय, बार-बार होने वाली हड़तालें रचनात्मक और कठोर सामूहिक सौदेबाजी

पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

हसरतों की चादर पे, प्यार की सिलवटें खुब भाती है। जैसे जैसे पड़ती है सिलवटें, चादर सिमटती जाती है। कब एक होजाती है, चादर और सिलवटें, बिस्तर को भी आहत नही होती। बस रह जाते है,कुछ निशान, सिलवटों के चादर पर, जिसे दुनिया सृजन की , पहचान कहती है। - अजय श्री

मुख्तलिफ़ गुज़लें जिस दिन से कहने लगा। महफ़िलों में भी तह्म मैं रहने लगा। इन रांगों में लहू खौलता है मगर अपने बच्चों की खातिर मैं सहने लगा। एक हल्की किरण रौशनी की दिखी तो अंधेरा का खंखर भी ढहने लगा। मेरे दामन में कौंटे भरे लोगों ने मुस्कुराकर मैं सब दर्द सहने लगा। आँखों ने आँसुओं को इजाजत न दी दिल के सहरा में दरिया ही बहने लगा।

- अंशु विनोद गुप्ता

महिमा भातवर्ष की, उन्हें न आई रास । निकल रही है कलम से,जिनके आज भड़सा ॥ करे लेखनी वाल पर ,द्वेषपूर्ण हर कार्य । कहलाएँ साहित्य के, वे भी द्रोणाचार्य ।। इर्ष्या जिनके खून में, हरकत से मतिमंद । करने वाले कर रहे, फिर भी उन्हें पसंद।। - रमेश शर्मा वशिष्ट

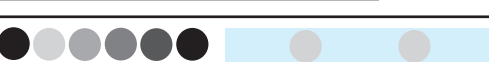
अपनी दुआओं में मेरा ख्याल रखना अपने दिल की दुनिया आबाद रखना संग तुम्हारे हम रहे ना रहे मार मेरी रूह तेरे साथ है ये याद रखना वो इन्तदाए़ इश्क़ और आगाजे हमनशीनी इन्ही यादों से सुबह - शाम सजाए़ रखना हर पल तुम पाओगे मेरे लमिस का एहसास बस गोशा-ए-तन्हाई में मुझे तुम याद रखना...

- डेजी जयसवाल

चिकित्सा के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? 5) हिटेश गुलिया ने ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में कौन सा पदक जीता?



गुप्ता (५) प्रदर्शक (४) खूबसूरत (६) भाषा शब्द शब्द (८) शब्दशाला 'क़ा' खलाल ख़ुला (1) -ख़ाख़ाख़



सदनों में जनता के प्रति जनप्रतिनिधियों का रवैया

भारत में मुख्य जनप्रतिनिधियों में लोकसभा के 543 निर्वाचित सांसद और राज्यसभा के 245 (233 निर्वाचित .12 मनीनीत) सदस्य शामिल हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा, राज्यों की विधानसभाओं में कुल 4,120 विधायक होते हैं। 18वीं लोकसभा (2024–2029) में कुल 543 सांसद चुने गए हैं। यानि देश का केन्द्र एवं राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वालों की संख्या कम नही है। लेकिन सत्तापक्ष और विपक्ष जिस तरह से सदन में जनभावनाओं से प्रेरित, देश विकास में समर्पित मुद्दों से भटककर आरोप प्रत्यारोप में सदन का वक्त जाया करने के साथ जनता की गद्दी कमाई बरबाद करता है वह वाकई जनता के लिए पीड़ा करी है।

चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा के बजाय हंगामा और असंबंधित बातों से कार्यवाही बाधित करना पूरी तरह गलत है। सत्ता पक्ष और विपक्ष जन मुद्दों को छोड़कर एक दूसरे के चरित्र, कमजोरी लेकर जो दांल कर रहे है वह ठीक नही



है। देश की जनता सब देख रही है।

आज भारत की संसद और विधानसभाओं में हंगामा है। देश को चलाने वाले नेता एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं। वे भूल रहे हैं कि लोकतंत्र को चलाना उनका दायित्व है. पहले संसद का, फिर लोकतंत्र का मखौल उड़कर, प्रतिष्ठ गिराकर उनका भी लाभ नहीं होगा।जनप्रतिनिधियों को सदन की गरिमा बनाए रखते हुए जनभावनाओं और जनता के विश्वास को याद रखना अनिवार्य है। उन्हें शोर-शराबे और नियोजित गतिरोध के बजाय सार्थक चर्चा और संवाद के माध्यम से व्यापक जनहित के मुद्दों का समाधान करना चाहिए। संसद और विधानसभा संवाद और विकास का मंच है, जहाँ जनप्रतिनिधियों का दायित्व जनभावनाओं को आवाज देना है, न कि व्यवधान डालना। सदनों की मर्यादा के अनुकूल आचरण करना और देश की अपेक्षाओं को पूरा करना प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का प्राथमिक कर्तव्य है।जनकल्याण की प्रतिबद्धतारू जनप्रतिनिधियों को

निर्वाचित क्षेत्र और संपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित रहकर कर्म करना चाहिए। अगर ये नेता लोकतंत्र की रक्षा न कर सकें तो उन्हें सार्वभौम अधिकार लेने का कोई हक नहीं. लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना उनका मकसद नहीं होना चाहिए। संसद और विधानसभाओं में जाने वाली देश की प्रमुख पार्टियां हैं, जो बदल बदल कर सरकार चलाती हैं। उन्हें सदन में और सदन के बाहर अपने आचरण पर विचार करना चाहिए। देश में ही नहीं विदेशों में भी उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वैसे तो राजनीति का अभिप्राय राजकाज चलाने वाली नीति से है।

इसकामकसद समतामूलक सुसभ्य समाज का निर्माण करना और देश के चहुँमुखी विकास में योगदान देना है। लेकिन दुर्भाग्य से अपने देश में राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। यह क्षरण कहां जाकर थमेगा, पुख्ता तौर पर कोई नहीं कह सकता। यह गिरावट एक दिन में नहीं आयी है। आजादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं और नीति नियंताओं ने काफी सोच-विचार कर समाज और देश के विकास का सपना देखा था। तब हमारी गिनती एक लुटे-पिटे गरीब देशों में होती थी। आज हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होने का दावा करते हैं, लेकिन नैतिक तौर पर तेजी से पाताल की ओर गिरते जा रहे हैं। सबसे खास बॉत यह कि आज का दौर डिजीटल मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है। इस दौर में सामान्य विधायक से लेकर खास विधायक सांसद, मंत्री, नेता सदन, नेता विपक्ष, स्पीकर तथा अन्य जिम्मेदारों की बात, हावभाव किसी ना किसी तरीके से आम जनता को देखने,सुनने मिल जाते है। उनका पक्षपात, जनता के प्रति गैरजिम्मेदारी भरा बयान या हरकत सबकुछ रिकार्ड होती रहती है इसके बावजूद सत्तापक्ष और जिस तरह जनविरोधी आचरण सदनों में कर रहा है वह भगवान तुल्य कहे जाने वाले मतदाता और आम जनता के साथ सीधे धोखा है। यानि इतना तय है कि जनता के प्रति अपनी जबाबदेही के लिए पक्ष विपक्ष अपने आप को अलग नहीं बता सकता।

सीमित नहीं रहते। औद्योगिक उत्पादन प्रभावित होता है, दैनिक यात्रियों को गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ता है, और सड़क किनारे के विक्रेताओं, घरेलू श्रमिकों और छोटे सेवा प्रदाताओं की आजीविका बाधित हो जाती है। इन श्रमिकों के लिए, केवल एक दिन की आय का नुकसान भी आजीविका संकट पैदा कर सकता है, उन्हें अपनी सीमित बचत को खत्म करने तथा गंभीर आर्थिक असुरक्षा में जाने के लिए मजबूर कर सकता है। भारत जैसी उमरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में, श्रमिक संघों (ट्रेड यूनियन) को संवाद, आपसी-बातचीत और नियोक्ताओं तथा सरकार के साथ रचनात्मक सहयोग को प्राथमिकता देना चाहिए। स्थायी सौदेबाजी और सहयोगात्मक समस्या समाधान पर आधारित एक मॉडल उत्पादन, रोजगार, और समग्र आर्थिक वृद्धि को बाधित किए बिना श्रमिकों की समस्याओं का समाधान कर सकता है। वर्तमान संदर्भ में, भारतीय केंद्रीय श्रमिक संघों को, जो धीरे-धीरे अपना प्रभाव खो रहे हैं, आत्मविश्लेषण करने और अन्यत्र अपनाई जाने वाली अधिक प्रभावी और दूरदर्शी तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है।

भारतीय श्रमिक को एक समग्र दृष्टिकोण के साथ संगठित किया जाना चाहिए, जो जीवन यापन में आसानी, सामाजिक सुरक्षा और सकारात्मक सहभागिता पर जोर देता हो। विवादों का समाधान टकराव के बजाय संवाद के माध्यम से करना यह सुनिश्चित करेगा कि परिचालन प्रक्रिया बाधित न हो और राष्ट्रीय विकास की गति सुचारु रूप से जारी रहे। केवल ऐसे संतुलित और व्यावहारिक रणनीतियों के जरिये ही श्रमिकों के अधिकारों को वास्तविक रूप में मजबूत और दीर्घावधि में सुरक्षित किया जा सकता है।



बार-बार चाँदी के पाजेब के ऐंड आ रहें, सोच रही हूँ ,बहु के लिए 2-4 पाजेब,बिछुये खरीद कर रख दूँ , नहीं तो 15- साल बाद बहु से जब भी लड़ाई होगी , बोलेंगी उस समय सोने में आग लगी थी मम्मी जी, थोड़ी बहुत चांदी ही खरीद लेती। - तनु देहलवी

21 वीं सदी में गोपनीयता जहां है वहीं कुछ गड़बड़ है, पारदर्शिता ही स्वच्छ व्यवहार है...समय के साथ सारे रहस्य खुल जाते है। प्रभु जैसी तकनिक की क्षमता अद्भुत ही है, आर्टिकल लेजर आधारित,स्टारलिक हाई स्पीड प्रोवाइडर नेटवर्क के साथ है ही...विकसित देश इस तकनिक का बढ़िया उपयोग कर रहे है।

- पोखराज शर्मा

राशि फल



पं. देवव्रत शर्मा

धीनी रहेगी। घरेलू आवश्यकता पूर्ति करने में असमर्थ अनुभव करेंगे। वृषः आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा। प्रातः काल किसी योजना के पूर्ण होने से धन आगम होगा। आज दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी कार्य भी समय से पूर्ण होंगे लेकिन यात्रा का मन बनने से आवश्यक कार्य में बरबाद करना पड़ेगा। मिथुनः आज धन की प्राप्ति जितनी सुगम रहेगी खर्च भी उतनी ही जल्दी हो जाएगा। खर्चा पर नियंत्रण ना रहने से आर्थिक उलझने बनेंगी।

कर्कः आज दिन का पूर्वा्र व्यस्तता से भरा

रहेगा। व्यवसायी एवं नौकरी वाले लोग अपूर्ण कार्य पूर्ण करने का भरपूर प्रयास करेंगे फिर भी कुछ कार्य अधूरे रह सकते है। सिंहः आज आपकी दिनचर्या आर्थिक कारणों से उत्थल-पुथल रहेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि रहने पर भी कागवाता की कमी रहेगी कार्यों को बेगन से कराने के कारण आरम्भ करने से पहले ही सफलता के प्रति आशंकित रहेगे।

कन्याः आज का दिन भी शुभ फलो की प्राप्ति कराएगा। छोटी-छोटी बातों पर क्रोध वाले स्वभाव पर अंकुश लगाएं प्रेम संबंध में खटास बनेगी। कार्य क्षेत्र पर सहकर्मी अथवा अन्य लोगो के आश्रित रहना पड़ेगा फिर भी जरूरत के अनुसार लाभ अदर्थ हो जायेगा।

तुलाः आज का दिन भी आप सुख शांति से व्यतीत करेंगे। कार्य व्यवसाय में छोटी-मोटी बाधाएं आती रहेगी लेकिन आप इनकी परवाह नहीं करेंगे।

वृश्चिकः आज आप दिन भर मन ही मन

खयाली पलाव पकाएंगे इनको सार्थक बनाने के लिए कोई ना कोई अनाव बाधा डालेगा। संघटा पलावत मनोरंजन के अवसर उललख होंगे।

धनुः आज के दिन आपको प्रत्येक कार्यों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दोपहर तक दिनचर्या सामान्य रहेगी। जोड़ तोड़ करके कार्य चलते रहेंगे।

मकरः आज का दिन आपको लगभग सभी कार्यों में सफलता दिलाएगा जहां असफल होंगे वहां कारण किसी अन्य की दखलंदगी रहेगी। महिलाए को कार्य बोझ के कारण झिड़की रहेगी।

कुंभः आज का दिन आपको सरकारी पक्ष से लाभ कराएगा आर्थिक स्थिति भी पहले से ज्यादा बेहतर रहेगी। खर्च भी अनावश्यक रहेगे दिखाते

ज्याद खर्च करेंगे।

मीनः आज के दिन आपके मन ने कुछ ना कुछ उड़े-बुल लगी रहेगी। किसी बड़े कार्य को करने की योजना बनाएंगे लेकिन आर्थिक कारणों से पीछे हटना पड़ेगा।



